शेव बक्स मोहता और अन्य

बनाम

बंगाल ब्रेवरीज लिमिटेड और अन्य

(जफर इमाम, ए. के. सरकार और रघुबर दयाल, जे.जे.)

15 सितम्बर 1960

निष्पादन कार्यवाही-कब्ज़े की डिलीवरी स्वीकार किए गए निष्पादन मामले को खारिज कर दिया गया-यदि आगे की निष्पादन कार्यवाही अनुमत है-प्रत्यर्थी के हित का खरीदार-क्या इसे पक्षकार-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), के रूप में जोड़ा जा सकता है। ऑर्डर 21, नियम. 35, धारा. 146.

एक निष्पादन कार्यवाही में अपीलार्थी डिक्री-धारकों ने कब्ज़े की डिलीवरी को स्वीकार कर लिया और अदालत के नज़ीर को एक रसीद प्रदान की जिसमें उन्हें कब्ज़े की सुस्त डिलीवरी को स्वीकार किया गया था, लेकिन उत्तरदाताओं, बंगाल ब्रुअरीज को उनकी अनुमति से कब्जे में रहने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी ने निष्पादन मामले को इस आधार पर खारिज करने की भी अनुमति दी कि प्रत्यर्थियों द्वारा उन्हें शांत कब्जा दिया गया था। इसके कुछ समय बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ निष्कासन के लिए निष्पादन के लिए एक नया आवेदन किया, जिसका एस के तहत विरोध किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 में आरोप लगाया गया है कि जहां तक उनका संबंध है, डिक्री को पहले की निष्पादन कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूरी तरह से निष्पादित किया गया था जो समाप्त हो गई थी और आगे के निष्पादन की कानून में अनुमति नहीं थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि डिक्री धारक के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 35 के तहत कब्जे वाले व्यक्ति को वास्तविक रूप से हटाए बिना

कब्जे की डिलीवरी स्वीकार करने का अधिकार है। यदि वह ऐसा करता है तो वह इस स्थिति के लिए बाध्य है कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित किया गया है, और इसे अब और निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सोइल बाला डस्सी बनाम निर्मला सुंदरी डस्सी के सिद्धांत पर, जिसमें अपील से पहले की गई खरीद के तहत अपीलकर्ता से खरीदार को अपील के अभिलेख पर लाया गया था, अपील से पहले किए गए हस्तांतरण के तहत प्रत्यर्थी से एक खरीदार को अपील के अभिलेख पर लाया जा सकता है।

इसके बाद शैला बाला डस्सी बनाम निर्मला सुंदरी डस्सी, (1958) एस. सी. आर. 1287 आया। महाराजा] अगस्त्य नाथ राय बनाम नजर चंद्र पारैननिक, (1930) 35 सी. डब्ल्यू. एन. 12, अनुमोदित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 58/1958

अतिरिक्त उप-न्यायाधीश-IV, 24 परगना, अलीपोर के विविध मामला सं. 15/1951 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 20 मई, 1953 के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपील संख्या 206/1953 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 5 अप्रैल, 1955 से उत्पन्न।

जी. के. डाफ्टरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, बी. अग्रवाल और सुकुमार घोष अपीलार्थियों की ओर से।

एच. एन. सान्याल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और आर. दत्ता, उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 के लिए।

15 सितंबर, 1960

न्यायालय का निर्णय सरकार, जे. द्वारा दिया गया।

यह अपील निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होती है। अपील को डिक्री-धारकों द्वारा दायर किया जाता है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसमें अलीपोर में एक विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया जाता है, जिसमें निष्पादन के लिए एक निर्णय-देनदार की आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डिक्री को पहले पूरी तरह से निष्पादित किया गया था, इसके निष्पादन के लिए वर्तमान कार्यवाही अक्षम थी और इसके बाद डिक्री धारकों की निष्पादन के लिए याचिका खारिज कर दी गई। सवाल यह उठता है कि क्या डिक्री को पहले पूरी तरह से निष्पादित किया गया था।

तथ्य इस प्रकार प्रतीत होते हैंः - 1944 से कुछ समय पहले एक सुकेश्वरी की मृत्यु हो गई थी, जिसके पास कलकत्ता के बाहरी इलाके में 26, 27 और 28, दम दम काशीपुर रोड के तीन भूखंड थे। उसने एक वसीयत छोड़ी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 6 निष्पादक थे। निष्पादकों ने प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5 को भूमि के इन विभिन्न भूखंडों के पट्टे दिए और उन्हें कब्जे में ले लिया। मोहता नामक कुछ व्यक्तियों, जिनके हितों का प्रतिनिधित्व वर्तमान अपील में अपीलकर्ता करते हैं, ने दावा किया कि सुकेश्वरी का केवल जीवन हित था-उन भूमि में, जो उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया और इसलिए निष्पादकों को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने 15 सितंबर, 1954 को अलीपुर में एक अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में निष्पादकों और किरायेदारों के खिलाफ एक आदेश के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्रतिवादियों को भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादियों को बेदखल करके भूमि पर कब्जा करने का अधिकार है। 30 मार्च, 1948 को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने मोहताओं के पक्ष में खास कब्जे के लिए एक आदेश पारित किया और प्रतिवादियों को भूमि पर लगाए गए ढांचे को हटाने के लिए

छह महीने का समय दिया। यह इस डिक्री का निष्पादन है जिसके साथ अपील का संबंध है।

प्रतिवादी संख्या 3 ने इस डिक्री से अपील की और वह अपील उन कारणों से सफल हुई, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाई देते हैं। प्रतिवादी संख्या 3 को आगे संदर्भित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम उसके साथ इस अपील में कोई संबंध नहीं पाते हैं। हालाँकि यह कहा जा सकता है कि उसके पास परिसर संख्या 26 था और उसके खिलाफ निष्पादन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है।

निष्पादक प्रतिवादियों ने भी डिक्री के खिलाफ अपील की। अन्य दो किरायेदारों, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने अपील नहीं की। इन किरायेदारों में से हम केवल प्रतिवादी संख्या 4, बंगाल ब्रुअरीज लिमिटेड से संबंधित हैं, जो डिस्टिलर के रूप में व्यवसाय करने वाली कंपनी है। यह परिसर संख्या 27 के कब्जे में था, जिस पर उसने शराब और खमीर के आसवन के लिए एक कारखाना बनाया था। प्रतिवादी संख्या 5 के पास परिसर संख्या 28 था, जिस पर कुछ मंदिर थे।

22 सितंबर, 1948 को मोहताओं, डिक्री धारकों ने प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 और 6 के खिलाफ डिक्री के निष्पादन के लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। 25 सितंबर को, अर्जित अधीनस्थ न्यायाधीश ने डिक्री-धारकों को 27 और 28 नंबर के परिसर के कब्जे के वितरण के लिए एक रिट जारी करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसमें डिक्री से बंधे किसी भी व्यक्ति को हटा दिया गया, जिसने उसे खाली करने से इनकार कर दिया और रिट में वापसी करने के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की गई। 28 सितंबर को, डिक्री धारकों ने डिक्री को निष्पादित करने के लिए पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के पास आवेदन किया। 29 सितंबर को, निष्पादक प्रतिवादियों ने उच्च

न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए निष्पादन पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 ने भी दो महीने के लिए निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन किया ताकि वह इस बीच डिक्री-धारकों के साथ एक व्यवस्था पर आ सके। डिक्री-धारकों द्वारा अदालत को यह आश्वासन देने पर कि वे अगले दिन दोपहर 2 बजे तक डिक्री को निष्पादित नहीं करेंगे, निर्णय-देनदारों की इन दो याचिकाओं को 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

30 सितंबर, 1948 को स्थगन के लिए दो याचिकाओं को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था। निष्पादक प्रतिवादियों की याचिका के संबंध में, उन्होंने कहा कि उनके पास सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, आर. 5 को देखते हुए निष्पादन पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है और फिर उस याचिका को खारिज कर दिया। प्रतिवादी द्वारा समय के लिए याचिका सं। 4 को भी खारिज कर दिया गया था लेकिन इसके संबंध में आदेश में निम्नलिखित अवलोकन दिखाई देता हैः "डिक्री-धारक वचन देते हैं कि वे कंपनी को अब से छह सप्ताह तक सामान्य व्यवसाय करने की अनुमति देंगे, उस समय तक कंपनी डिक्री धारकों के साथ मामले का निपटारा कर देगी।" इसके बाद उसी दिन डिक्री धारकों ने अदालत में डिक्री को निष्पादित करने के लिए पुलिस सहायता के लिए आवश्यक लागत जमा की और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने पुलिस से 1 अक्टूबर, 1948 को आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। यह भी प्रतीत होता है;, बाद में उसी दिन प्रतिवादी, नहीं। 4 ने निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक और याचिका दायर की और निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए संहिता की धारा 47 के तहत एक याचिका भी दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके और डिक्री-धारकों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था थी कि वह आई. टी. एस. का भुगतान करेगा। 150 मासिक किराए के रूप में और इसे डिक्री की वैधता को चुनौती देने के लिए किसी भी अपील को दायर करने की आवश्यकता

होती है। डिक्री धारकों ने प्रतिवादी नं. द्वारा इन याचिकाओं का विरोध किया। 4. विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने उन पर कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्हें 11 नवंबर, 1948 तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मामले की जांच की आवश्यकता है।

1 अक्टूबर, 1948 को न्यायालय के नाजीर कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ रिट के संदर्भ में डिक्री को निष्पादित करने के लिए 27 और 28 नंबर के परिसर में गए। हो ने परिसर संख्या 27 का द्वार बंद पाया लेकिन बाद में प्रतिवादी संख्या 4 के प्रबंधक ने उसके अनुरोध पर इसे खोल दिया। इसके बाद जो हुआ वह नज़ीर की वापसी से प्रकट होता है जो निम्नलिखित शब्दों में हैः "फिर हमने कारखाने के घर में प्रवेश किया और लगभग सुबह 10:30 बजे प्रत्येक इमारत पर कब्जा कर लिया। उन इमारतों से फर्नीचर और अन्य चल वस्तुओं को हटाने से पहले डिक्री-धारकों और कारखाने के प्रबंधक के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता था कि कारखाना 6 सप्ताह तक अपना सामान्य व्यवसाय चलाएगा और इस बीच कारखाने का कार्यकारी निकाय डिक्री-धारक के साथ समझौता करेगा और डिक्री धारकों के कुछ लोग वहां गार्ड के रूप में रहेंगे। यह स्वीकार किया जाता है कि डिक्री-धारकों के गार्ड को उसके बाद परिसर में तैनात किया गया था।

इसके बाद नाजीर परिसर संख्या 28 की ओर बढ़ा और वापसी से यह भी पता चलता है कि उसने इन परिसरों का कब्जा डिक्री-धारकों को सौंप दिया था। वापसी का प्रासंगिक हिस्सा इन शब्दों में हैः "फिर हम 2 मंदिरों वाले परिसर संख्या 28 (पुराना संख्या 8) की ओर बढ़े और पाया कि मंदिर के पुजारी मौजूद थे। वह सौहार्दपूर्ण ढंग से परिसर से बाहर आ गया और अभिलेख में उल्लिखित मंदिरों, हाथों, तालाबों और अन्य भूखंडों पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा दिए जाने के बाद, डिक्री धारकों ने उसी दिन कब्जे की स्वीकृति में एक रसीद निष्पादित की जो उन्हें प्राप्त हुई थी। वह रसीद इन शर्तों में है

"श्री भबतरन बनर्जी, नायब नाजीर, जिला न्यायाधीश न्यायालय, अलीपुर, 24 से प्राप्त। परगना, परिसर संख्या 7 और 8 (पूर्व में। 27 और 28) उपरोक्त निष्पादन मामले में दम दम कॉसिप्योर रोड, आज सुबह 10:30 पर सभी इमारतों, तालाबों, बगीचों और मंदिरों आदि सहित, ये सभी अपनी अनुसूची में लिखित में उल्लिखित हैं।

रसीद गलती से परिसर को "पूर्व में" परिसर के लिए संख्या 27 और 28 के रूप में वर्णित करती है, जिस पर ये संख्याएँ होती हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1 अक्टूबर, 1948 को पूर्वाह्न में निष्पादक प्रतिवादियों ने डिक्री से उनके द्वारा दायर अपील में निष्पादन पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने एक विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। यह आदेश दिए जाने के बाद निष्पादक प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्पादन पर रोक के बल पर परिणामी आदेशों के लिए उसी दिन विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश का रुख किया। इसके बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश दियाः "विशेष परिस्थितियों में रिट को अस्थायी रूप से याद करें। यदि इस बीच औपचारिक स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होता है तो नए सिरे से विचार के लिए 5 नवंबर, 1948 तक। यह आदेश निष्पादक प्रतिवादियों के वकीलों के मौखिक प्रतिनिधित्व पर पारित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने निष्पादन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश को औपचारिक रूप से तैयार करने और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का समय नहीं था।

22 नवंबर, 1948 को, जो रिट के निष्पादन के लिए वापसी करने के लिए निर्धारित दिन था, निष्पादन मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया प्रतीत होता हैः "कब्जा दिया गया। एक तीसरे पक्ष ने आवेदन दायर किया है। 21, आर। 100, सी. पी. सी. विभिन्न मामलों के निपटारे के

बाद निष्पादन का मामला रखा जाए। 1948 का मामला सं. 13 ,1948 का विविध मामला संख्या 13 या के तहत तीसरे पक्ष की याचिका पर शुरू किया गया था। 21, आर। संहिता का 100, निष्पादन द्वारा उन्हें हटाने पर आपत्ति जताते हुए। यह तीसरा पक्ष एक भैरब तिवारी था और वह संभवतः परिसर संख्या 28 में कुछ अधिकार का दावा कर रहा था क्योंकि परिसर संख्या 27 पर उसका कोई दावा करने का कोई सवाल ही नहीं था जो विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे में था।

निष्पादक प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा 1 अक्टूबर, 1948 को जारी विज्ञापन अंतरिम रोक अंतिम सुनवाई के लिए आई और इसके परिणामस्वरूप 21 जनवरी, 1949 को निम्नलिखित आदेश आया।

"यदि लागतों के कारण कुछ भी देय है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो वह राशि प्रतिवादी संख्या 4 (यानी श्री सेन के मुवक्किल) द्वारा एक महीने के भीतर नीचे दिए गए न्यायालय में जमा की जाएगी, वह मशीनरी को हटाने और भूमि के उस हिस्से को खाली करने के लिए देगा, जिस पर वह पट्टेदार के रूप में कब्जा कर रहा है और जिसे वह अभी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जमा किए जाने की चूक और ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार परिसर खाली करने की चूक में, यह नियम समाप्त हो जाएगा।

हम किसी भी अन्य वस्तु के संबंध में कब्जे के वितरण पर रोक नहीं लगाते हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 या संख्या 1 या किसी अन्य प्रतिवादी को छोड़कर और प्रतिवादी संख्या 3 को छोड़कर रुचि है।"

इस आदेश में दर्ज पक्षों की उपस्थिति से यह नहीं पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा इसके संबंध में कोई उपस्थिति दर्ज कराई गई है। नंबर 4. अभिलेखों से यह प्रतीत नहीं होता है कि निष्पादक प्रतिवादियों द्वारा अपील में कौन सी अन्य कार्यवाही, यदि

कोई हो, ली गई थी, लेकिन यह सहमति है कि उस अपील को 8 सितंबर, 1954 को खारिज कर दिया गया था।

प्रतिवादी संख्या 4 ने 21 जनवरी, 1949 के आदेश में उल्लिखित तीन महीनों के अंत में खाली नहीं किया। इसके बाद पक्षों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंड न्यायालयों में कार्यवाही की। इन कार्यवाहियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है और यह कहना पर्याप्त है कि उन्होंने परिसर संख्या 27 के कब्जे को प्रभावित नहीं किया। प्रतिवादी सं। 4, जो तब तक कब्जे में रहा जब तक कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कब्जा नहीं ले लिया जैसा कि इसके बाद कहा गया है।

8 सितंबर, 1949 को, निष्पादन मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः "डिक्री-धारक कोई अन्य विराम नहीं लेता है। जहां तक बंगाल ब्रोवरीज का संबंध है, कब्जा दिया गया है।

आदेश

निष्पादन के मामले को आंशिक संतुष्टि पर खारिज कर दिया जाए। 27 सितंबर, 1951 को डिक्री-धारकों ने प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ परिसर संख्या 27 से उसे बेदखल करके निष्पादन के लिए एक नया आवेदन किया। प्रतिवादी सं. 4 ने एस के तहत निष्पादन के खिलाफ आपत्ति जताई। संहिता की धारा 47 में आरोप लगाया गया है कि जहां तक इसका संबंध है, डिक्री को पहले की निष्पादन कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूरी तरह से निष्पादित किया गया था, जिसे 8 सितंबर, 1949 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और यह कि आगे का निष्पादन कानून में अनुमेय नहीं था, इस आपत्ति से यह है कि वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है और निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या इस तरह से उठाए गए निष्पादन पर आपत्ति सही है। जैसा कि पहले

कहा गया था, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने निष्पादन पर आपत्ति को खारिज कर दिया लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय ने उनके आदेश को रद्द कर दिया और निष्पादन के लिए याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 15 जून, 1956 को इस न्यायालय में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया और 3 अगस्त, 1956 को उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि अपील को स्वीकार किया जाए।

11 अगस्त, 1960 को इस अदालत द्वारा मूल चंद सेठिया, तोला राम सेठिया और हुलास चंद बोथरा नाम के तीन व्यक्तियों को इस अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया था। हालाँकि आदेश में प्रावधान किया गया था कि अपीलकर्ता डिक्री-धारकों को अपील में इन व्यक्तियों के स्थान पर आपत्ति करने का अधिकार होगा। हमारे सामने सुनवाई में केवल ये अतिरिक्त पक्ष अपील को चुनौती देने के लिए उपस्थित हुए। अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि जोड़े गए पक्षों का कोई अधिकार नहीं है और अपील में उनकी सुनवाई नहीं की जा सकती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने कोमिला बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक बैंक को सभी संरचनाओं और सहायकों के साथ परिसर संख्या 27 के तीन क्रमिक बंधक निष्पादित किए थे। इनमें से पहले बंधक को 25 मई, 1944 को निष्पादित किया गया था, और अन्य दो बंधक को निष्कासन में मुकदमा दायर करने के बाद निष्पादित किया गया था, लेकिन इससे पहले कि उस मुकदमे का फैसला किया गया था। कोमिला बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परिसंपत्तियाँ बाद में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में निहित हो गईं। 1953 में कुछ समय के लिए, यूनाइटेड बैंक ने बंधक के प्रवर्तन के लिए एक मुकदमा दायर किया। 30 मई, 1955 को यूनाइटेड बैंक के पक्ष में एक अंतिम बंधक आदेश पारित किया गया था। 20 जुलाई, 1956 को गिरवी रखी गई संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया और यूनाइटेड बैंक द्वारा खरीदा गया। 1 मार्च,

1958 को बंधक बिक्री की पुष्टि की गई और बाद में यूनाइटेड बैंक को परिसर संख्या 27 के कब्जे में डाल दिया गया। 13 जुलाई, 1960 को यूनाइटेड बैंक ने इन अतिरिक्त उत्तरदाताओं को सभी संरचनाओं और अनुषंगियों के साथ परिसर संख्या 27 और उसमें अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित से अवगत कराया। यह इस हस्तांतरण के आधार पर है कि जोड़े गए उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय से 11 अगस्त, 1960 का आदेश प्राप्त किया, जिसमें उन्हें अपील का पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 4, बंगाल ब्रुअरीज लिमिटेड, अब परिसमापन में है और उसने इस अपील पर उपस्थिति दर्ज नहीं की है और न ही इसका बचाव करने के लिए कोई कदम उठाया है।

हमें ऐसा लगता है कि जोड़े गए उत्तरदाताओं को ठीक से रिकॉर्ड में लाया गया था। सैला बाला डस्सी बनाम निर्मला सुंदरी डस्सी (1) मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपील संहिता की धारा 146 के अर्थ के भीतर एक कार्यवाही है और इसके साथ एक अपील दायर करने का अधिकार है जो उस व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील को जारी रखने का अधिकार है जिसके तहत अपीलकर्ता ने दावा किया था और इस आधार पर अपील के रिकॉर्ड पर अपील से पहले की गई खरीद के तहत अपीलकर्ता से एक खरीदार लाया गया था। हम सोचते हैं कि इसी सिद्धांत पर हमारे सामने मामले में जोड़े गए उत्तरदाताओं को ठीक से रिकॉर्ड में लाया गया था।

यह विवाद में नहीं है कि यदि डिक्री एक बार प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ पूरी तरह से निष्पादित की गई थी, तो इसे प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ पूरी तरह से निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो इसे परिसर संख्या 4 के संबंध में फिर से निष्पादित नहीं किया जा सकता है। 27. दूसरे शब्दों में, यदि अधिकार 1 अक्टूबर 1948 को डिक्री के निष्पादन में डिक्री धारकों को पूरी तरह से सौंप दिया गया था, तो डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट हो गई होगी और आगे के निष्पादन द्वारा प्रवर्तन के लिए

इसका कुछ भी नहीं बचा है। यह डिक्री खास के कब्जे के लिए थी और इस संहिता के आदेश 21 नियम 35 के तहत इसके निष्पादन में संबंधित संपत्ति के कब्जे को डिक्री-धारकों को, यदि आवश्यक हो, तो डिक्री द्वारा बाध्य किसी भी व्यक्ति को हटाकर, जो संपत्ति को खाली करने से इनकार कर देता था, वितरित किया जाना था।

कार्यवाही के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस तरह का कब्जा दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 अधिकार में पक्ष था और डिक्री से बंधा हुआ था। प्रतिवादी संख्या 4 के संबंध में 8 सितंबर, 1949 को दिए गए आदेश में कहा गया है, "जहां तक बंगाल ब्रुअरीज का संबंध है, कब्जा दिया गया है। यह डिक्री धारकों के लिए बाध्यकारी आदेश है। यह नहीं कहा गया है कि यह आदेश गलत था और न ही इसे किसी भी समय दरकिनार करने या किसी भी तरह से इसकी शुद्धता को चुनौती देने का कोई प्रयास किया गया है। 22 नवंबर, 1948 के आदेश के संबंध में भी यही स्थिति है, जिसमें नज़ीर की वापसी पर दर्ज किया गया है कि अधिकार रिट के संदर्भ में दिया गया था।

9 सितंबर, 1949 के आदेश में कोई संदेह नहीं है कि आगे कहा गया है, "आदेश दिया गया है कि निष्पादन के मामले को आंशिक संतुष्टि पर खारिज कर दिया जाए।" इस आदेश में "आंशिक संतुष्टि" शब्द, हालांकि स्पष्ट रूप से आंशिक संतुष्टि का उल्लेख नहीं करते हैं. जैसा कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ, बंगाल ब्रुअरीज, आदेश के लिए स्पष्ट रूप से कहता है, "जहां तक बंगाल ब्रुअरीज का संबंध है, कब्जा दिया गया है।" इसलिए बंगाल ब्रुअरीज लिमिटेड के खिलाफ और इसके परिणामस्वरूप उसके कब्जे में परिसर संख्या 27 के संबंध में आदेश को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया गया था। यहां तक कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, जिन्होंने निष्पादन को बनाए रखने योग्य माना था, ने पाया कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिक्री-धारकों को पहले कब्जा मिल गया था।" इसके बावजूद, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने फैसला किया कि डिक्री को अभी भी निष्पादित किया जा सकता है क्योंकि उनका विचार था कि 21 जनवरी, 1949 को

उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में, प्रतिवादी संख्या 4 ने "नायब नाजीर द्वारा कब्जे की डिलीवरी की अनदेखी की होगी और अब उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि नायब नाजीर द्वारा कब्जे की डिलीवरी कानूनी और वैध थी।" बाद में बताए जाने वाले कारणों से, हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं।

यह सच है कि नज़ीर की वापसी से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 4 को शारीरिक रूप से नहीं हटाया गया था। लेकिन उसी विवरणी से यह भी पता चलता है कि इसे इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि इसके और डिक्री-धारकों के बीच कुछ व्यवस्था हुई थी और क्योंकि डिक्री-धारकों को प्रतिवादी संख्या 4 को परिसर से हटाने की आवश्यकता नहीं थी। अब के तहत या। 21, आर। 35 क. डिक्री द्वारा अधिकृत और बाध्य व्यक्ति को केवल यदि आवश्यक हो, अर्थात्, यदि आवश्यक हो तो डिक्री धारक को वह अधिकार देने के लिए हटाया जाना चाहिए जिसका वह हकदार है और माँग करता है। यदि डिक्री धारक इस तरह का निष्कासन नहीं चाहता है तो कब्जे वाले व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह डिक्री धारक के लिए खुला है कि वह कब्जे में व्यक्ति को वास्तविक रूप से हटाए बिना उस नियम के तहत कब्जे की डिलीवरी स्वीकार कर सकता है। यदि वह यह बताता है, तो हो बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे वह अधिकार नहीं दिया गया है जिसका हो कानून के तहत हकदार था। इस मामले में ऐसा ही हुआ। वर्तमान मामले में डिक्री-धारकों को, उनकी अनुमति के साथ परिसर में प्रतिवादी संख्या 4 के साथ कब्जे की अपनी स्वीकृत डिलीवरी। उन्होंने कब्जे की पूरी डिलीवरी को स्वीकार करते हुए एक रसीद दी। उन्होंने 8 सितंबर, 1949 को निष्पादन के मामले को इस आधार पर खारिज करने की अनुमति दी कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उन्हें पूरा अधिकार दिया गया था। 'यह तथ्य कि उन्होंने अपने गार्डों को परिसर में रखा जैसा कि नज़ीर की वापसी में उल्लेख किया गया है, यह भी दर्शाता है कि उन्होंने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह डिक्री-धारकों के लिए इस तरह के कब्जे को स्वीकार

करने के लिए खुला था। एक बार ऐसा करने के बाद, वे इस स्थिति के लिए बाध्य हैं कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित कर दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इसे और निष्पादित नहीं किया जा सकता है। महाराजा जगदीश नाथ राय बनाम नफूर चंद्र परमानिक के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डिक्री आगे निष्पादन करने में सक्षम नहीं थी। पेज न 15 पर यह कहा गया

"इसलिए, यह मामला मुझे उन मामलों में से एक लगता है जिसमें एक डिक्री-धारक खुद को खास कब्जे के लिए एक डिक्री से लैस करके पहले उस डिक्री को केवल अपने किसी गुप्त उद्देश्य के साथ प्रतीकात्मक कब्जा प्राप्त करके निष्पादित करता है, और उसके बाद और दूसरी किस्त के रूप में खास कब्जे के लिए कहता है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के पाठ्यक्रम की कानून के तहत अनुमति है। मेरी राय है कि ऐसा नहीं है।"

हम पूरी तरह से उस विचार से सहमत हैं जो वहां व्यक्त किया गया था।

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि 30 सितंबर, 1948 के आदेश से पता चलता है कि डिक्री-धारकों ने प्रतिवादी संख्या 4 को छह सप्ताह के लिए सामान्य व्यवसाय करने की अनुमति देने का बीड़ा उठाया था और इसलिए, 1 अक्टूबर, 1948 को जब वे डिक्री को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े, तो वे प्रतिवादी संख्या 4 को हटाकर इसे पूरी तरह से निष्पादित करने की मांग नहीं कर रहे थे। 4 कब्जे से। उन्होंने कहा कि इसलिए 1 अक्टूबर, 1948 को निष्पादन पूरी नहीं हुई थी क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 को 29 सितंबर, 1948 को दिए गए वचन के अनुसार नहीं हटाया गया था। हम 8 सितंबर, 1949 को दिए गए आदेश या नाजीर की वापसी और डिक्री-धारकों द्वारा दी गई रसीद को वचन के कारण उनमें उपयोग किए

गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के विपरीत तरीके से पढ़ने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, यह डिक्री धारकों का मामला नहीं है कि वह आदेश, नज़ीर की वापसी या रसीद गलत है या किसी भी गलतफहमी के माध्यम से अस्तित्व में आई थी। इनमें से किसी की भी वैधता या शुद्धता को कभी चुनौती नहीं दी गई थी और न ही अब दी गई है। 8 सितंबर, 1949 का आदेश डिक्री धारकों के लिए बाध्यकारी है और वे अब इसकी शर्तों से पीछे नहीं जा सकते हैं। इसी कारण से, न तो वे 22 नवंबर, 1948 के आदेश के पीछे जा सकते हैं, जिसमें नज़ीर की वापसी के संदर्भ में दर्ज किया गया था कि कब्जा दिया गया था।

हमें आगे ऐसा लगता है कि यदि वचन का अर्थ यह होता कि प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से नहीं हटाया जाना था, तो निष्पादन पर रोक लगा दी जाती, जो कि ऐसा नहीं था, क्योंकि डिक्री को निष्पादित करने का एकमात्र तरीका प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से हटाना था क्योंकि यह केवल वास्तविक कब्जे में था, निष्पादक प्रतिवादी उससे केवल मकान मालिक के रूप में किराए का दावा कर रहे थे। फिर जिस आदेश में वचन दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ निष्पादन पर रोक, जैसा कि उसने कहा था, को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, आदेश पत्र से पता चलता है कि वचन पत्र दिए जाने के आदेश के तुरंत बाद उसी दिन एक और आदेश दिया गया था जिसमें डिक्री धारकों से निष्पादन में मदद करने के लिए पुलिस के खर्च की रसीद को स्वीकार किया गया था और निर्देश दिया गया था कि डिक्री के निष्पादन के समय 1 अक्टूबर, 1948 को किसी भी आवश्यक सहायता के लिए पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। सभी विभिन्न आदेशों, वापसी और रसीद में सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र संभावित तरीका इस आधार पर आगे बढ़ना है कि वचन पत्र द्वारा डिक्री-धारक इस बात पर सहमत हुए कि कब्जा करने के बाद, वे प्रतिवादी संख्या 4 को उनकी अनुमति से छह सप्ताह तक परिसर में अपना व्यवसाय

जारी रखने की अनुमति देंगे। इस तरह के उपक्रम से यह नहीं पता चलता है कि इसका उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से हटाना नहीं था।

विद्वान महान्यायवादी ने यह भी तर्क दिया कि यह तथ्य कि वचन केवल छह सप्ताह की अवधि तक सीमित था, यह दर्शाता है कि डिक्री धारक प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जा प्राप्त करने के बाद भी कब्जा में बने रहने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तब के लिए किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं किया गया होगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि डिक्री धारकों को डिक्री के तहत कब्जा प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 को किसी भी अवधि के लिए कब्जा में बने रहने की अनुमति देने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी अनुमति छह सप्ताह के लिए या किसी भी लंबी या छोटी अवधि के लिए हो सकती है जैसा कि डिक्री-धारक उचित समझते हैं।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तब तर्क दिया कि मामला वह था जिसमें डिक्री को एक दिन में आंशिक रूप से निष्पादित किया गया था और उस दिन समय की कमी या अन्य कारण से निष्पादन रोक दिया गया था, जिसका उद्देश्य इसे अगले दिन जारी रखना था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में, उसी डिक्री के बाद के निष्पादन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा. हमें ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान मामला इस प्रकृति का है, रिकॉर्ड पर आदेश और दस्तावेज इस दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। आगे का निष्पादन पहले के निष्पादन के दौरान नहीं है, बल्कि एक नया निष्पादन है। निष्पादन में बाधा दो साल से अधिक समय तक थी अन्य बातों के अलावा, डिक्री-धारकों द्वारा परिसर में अपने स्वयं के गार्डों को रखना केवल इस आधार पर हो सकता है कि उन्होंने कब्जा कर लिया था. विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने कहा कि गार्डों को प्रतिवादी संख्या 4 की अनुमति से वहां रखा गया था। नज़ीर की वापसी पूरी तरह से इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ है। वास्तव में, यह बताना मुश्किल है कि प्रतिवादी संख्या 4 परिसर में डिक्री-धारकों के गार्डों को अनुमति क्यों देगा, जब तक कि यह इस आधार पर नहीं था कि

डिक्री-धारकों द्वारा कब्जा ले लिया गया था और गार्ड उनके कब्जे की रक्षा के लिए थे। गार्डों को बाद में हटा दिया गया था लेकिन यह रिकॉर्ड से नहीं पता चलता है कि उन्हें किन परिस्थितियों में हटाया गया था।

न ही हमें लगता है कि 1 अक्टूबर, 1948 का आदेश डिक्री धारकों की सहायता करता है। उस आदेश ने रिट को अस्थायी रूप से वापस लेने का निर्देश दिया। आदेश पूरी तरह से निष्फल था क्योंकि रिट को पहले विधिवत निष्पादित किया गया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे। यह, जैसा कि हमने कहा है, निष्पादन मामले के अभिलेखों से भी स्पष्ट है। रिट को पूरी तरह से निष्पादित करने के बाद वापस नहीं लिया जा सका। न ही आदेश यह स्थापित करता है कि डिक्री को केवल आंशिक रूप से निष्पादित किया गया था। डिक्री के पूर्ण रूप से निष्पादित होने से पहले रिट को वास्तव में वापस नहीं लिया गया था। 8 सितंबर, 1949 के आदेश में यह मानना असंभव है कि रिट को केवल आंशिक रूप से निष्पादित करने के बाद वापस ले लिया गया था

विद्वान सॉलिसिटर-जनरल द्वारा दिया गया दूसरा तर्क 21 जनवरी, 1949 के उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित था। यह कहा गया था कि उस आदेश ने संकेत दिया था कि प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से हटाकर डिक्री का निष्पादन नहीं किया गया था क्योंकि यह, वास्तव में, डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश था। यह भी कहा गया था कि आदेश प्रतिवादी संख्या 4 के अभ्यावेदन और इस निष्कर्ष के आधार पर होना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से हटाकर डिक्री को निष्पादित नहीं किया गया था। तर्क यह था कि निष्कर्ष और प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या 4 पर और इसलिए जोड़े गए उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी था और आगे यह कि इस आधार पर आदेश प्राप्त करने के बाद कि इसे निष्पादन में कब्जे से बेदखल नहीं किया गया था, प्रतिवादी संख्या 4 और इसलिए जोड़े गए उत्तरदाताओं को उस स्थिति को अनुमोदित

करने और पुनः प्रमाणित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और अब यह कहते हुए सुना जा सकता है कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित किया गया था। हम सोचते हैं कि ये दोनों तर्क निराधार हैं। आदेश स्पष्ट नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने किसी भी रोक के लिए कहा था, प्रतिवादी संख्या 4 ने डिक्री से अपील नहीं की थी। यह डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का हकदार नहीं था। यह डिक्री धारक की अनुमति से परिसर के कब्जे में था। अनुमति शुरू में छह सप्ताह के लिए थी जो अवधि समाप्त हो गई थी. यह निष्पादक प्रतिवादी थे जिन्होंने 1 अक्टूबर, 1948 को उच्च न्यायालय से एक विज्ञापन अंतरिम रोक प्राप्त की थी। यह आदेश निष्फल था क्योंकि इसे बनाए जाने से पैंतालीस मिनट पहले, आदेश को पूरी तरह से निष्पादित कर दिया गया था। उन परिस्थितियों में न्यायालय 21 जनवरी, 1949 को प्रतिवादी संख्या 4 के अनुरोध पर उसे परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दे सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 डॉक्स द्वारा अनुरोध, यदि सहयोगी है, तो इसमें यह अभ्यावेदन शामिल नहीं है कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित नहीं किया गया था। यह हो सकता है, अधिक से अधिक; इसका मतलब है कि डिक्री धारकों द्वारा शुरू में दी गई छह सप्ताह की अनुमति को और बढ़ाया जा सकता है। दूसरे तर्क के संबंध में, कि 21 जनवरी, 1949 का आदेश इस निष्कर्ष के बराबर है कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित नहीं किया गया था, हमें यह इंगित करना होगा कि ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता है। आदेश एक अंतर्वर्ती कार्यवाही पर किया गया था और केवल अपील में अंतिम निर्णय की सहायता के लिए था। जिस कार्यवाही में आदेश दिया गया था, उसमें इस मुद्दे का निर्णय शामिल नहीं था कि क्या डिक्री को पहले पूरी तरह से निष्पादित किया गया था। इसलिए आदेश में इस तरह के मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। यह आदेश हमारे विचार में

किसी भी तरह से जोड़े गए उत्तरदाताओं को यह तर्क देने से नहीं रोकता है कि डिक्री को पूरी तरह से निष्पादित किया गया था।

परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। हम लागत के बारे में कोई आदेश देना उचित नहीं समझते हैं।

याचिका खारिज कर दी गई

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।